

अब सिंधियों ने अलग ‘‘सिंधु देश’’ की माँग जोरों से उठाई पाकिस्तान में

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अब काफी मुखर व साहसी हो गये हैं, सिंधु देश की माँग को लेकर चल रहे आंदोलन, प्रदर्शन की ‘‘क्लिप’’ दिखाने में

—अंजन राॅय—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 17 मई। बलूचिस्तान के बाद अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी स्वतंत्रता की माँग उठने लगी है। पाकिस्तान के हैदराबाद को उत्तरी शहरों से जोड़ने वाले राजमार्ग को सिंधी प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया और ‘‘सिंधु देश’’ के नारे लगाते हुए पाकिस्तान की संघीय सरकार के खिलाफ धरना दिया।

सिंध के लोग अब अपनी अलग पहचान और अपनी भूमि को लेकर बेहद समर्पित और मुखर रूप से सामने आए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अब काफी मुखर व साहसी हो गए हैं, सिंधु देश की माँग को लेकर चल रहे, आंदोलन व प्रदर्शनों की क्लिप्स दिखाने में। ये क्लिप्स पूरे देश या प्रांतों में हो रहे प्रदर्शनों और रैलियों को दिखा रही हैं। सिंध प्रांत का हैदराबाद शहर अब सिंधी विरोध और स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है।

इन नारों की मूँज दक्षिणी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सुनाई दे रही है। सिंधी प्रदर्शनकारी, पंजाबियों द्वारा उनके क्षेत्र की ज़मीनों पर किए जा रहे कृषि कब्जे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कराची को सरकार पहले ही संघीय क्षेत्र घोषित कर चुकी है, जिसका सिंधी लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं।

आनन्द शर्मा, गौरव गोगोई, डॉ. सैय्यद नासिर व राजा बरार, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 17 मई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को बताया कि पाकिस्तान से भारत में की जाने वाली आतंकी घटनाओं के संबंध में भारत का पक्ष रखने के लिए अन्य देशों की यात्रा पर जाने वाले सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के लिए कांग्रेस ने चार सांसदों के नाम दे दिए हैं।

सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में रमेश ने बताया कि शुक्रवार सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजौजू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और

आप के 15 पार्षदों ने पार्टी छोड़ी

नयी दिल्ली, 17 मई। आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेतृत्व से नाराज 15 निगम पार्षदों ने शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

आप के वरिष्ठ पार्षद मुकेश गोयल ने कहा, हमारे 15 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है और अलग दल इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई है। पिछले ढाई साल में हम लोगों के काम नहीं कर पाये। हमारा पूरा समय लड़ाई-झगड़े में बीता है। पार्षदों के इस्तीफा में कहा गया है कि हम सभी निगम पार्षद दिल्ली नगर निगम में वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी के

- इन्हें शिकायत है कि पार्टी में इतना लड़ाई झगड़ा है कि वे जनता के काम नहीं कर पाए।

टिकट से चुने गये थे, लेकिन 2022 में दिल्ली नगर निगम में सत्ता में आने के बावजूद, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निगम को सुचारु रूप से चलाने में असमर्थ रहा। शीर्ष नेतृत्व का निगम पार्षदों से आपस में समन्वय न के बराबर रहा, जिसके कारण पार्टी विपक्ष में आ गयी।

पार्टी से इस्तीफा देने वालों में गोयल के अलावा, हेमचंद्र गोयल, हिमानी जैन, ऊषा शर्मा, अशोक पांडेय, राखी यादव, साहिब कुमार, राजेश कुमार, अनिल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सिंधी लोग मुख्य रूप से, पाकिस्तान के प्रशासन में पंजाबियों का भारी ‘‘आधिपत्य’’ सा होने से परेशान हैं। पंजाब व सिंध के बीच इस मसले पर विवाद व कड़ुता कई सालों से चल रही है।

- अब सिंध के लोग इस ‘‘आधिपत्य’’ को समाप्त करने के लिये मानसिक रूप से काफी समय से तैयार हैं तथा अपने अलग स्वतंत्र राज्य की माँग कर रहे हैं।

- बलूचिस्तान के ‘‘स्वतंत्रता’’ आंदोलन की सफलता से प्रेरित होकर सिंध की जनता भी अपने अलग ‘‘देश’’ की माँग पुरजोर ढंग से उठा रही है और माँग की पूर्ति के लिये, किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

सिंधी मूलतः उद्यमशील हैं और व्यापार में सफल रहे हैं और कराची पाकिस्तान का प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र है। लेकिन, पंजाबी वर्चस्व के कारण सिंधियों को सरकारी नौकरियों और नियुक्तियों में भेदभाव का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान सरकार में पंजाबी वर्चस्व बनाए रखने के कारण यह स्थिति बनी है।

सिंधी लोग, पाकिस्तान की राजनीति और प्रशासन में पंजाबियों के प्रभुत्व के विरुद्ध हैं। वे इस प्रभुत्व को समाप्त करने की माँग कर रहे हैं और सिंध की आजादी की माँग को खुलकर उठा रहे हैं। पंजाब और सिंध के बीच जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद

चल रहा है, जो अब और भी गहराता जा रहा है।

बलूचिस्तान में जो हो रहा है, उसे देखकर सिंधी भी अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस सप्ताह बलूचों के एक कट्टरपंथी धड़े ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और संघीय सरकार व सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसक हमले जेल कर दिए हैं।

बलूचों के उदाहरण से सिंधियों को हिम्मत मिली है और वे भी अब खुलकर स्वतंत्रता की माँग करने लगे हैं। हालाँकि, यह माँग वर्षों से दबे स्वर में चल रही थी, लेकिन, अब जब संघीय सरकार का नियंत्रण कमजोर होता जा रहा है है तो क्षेत्रीय और पृथकतावादी ताकतें अधिक

मुखर हो गई हैं तथा आशावादी महसूस कर रही हैं।

पाकिस्तान की सरकार ने यदा-कदा होने वाले विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ कठोर रवैया अपनाया था। कई आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया गया और कई राष्ट्रवादी नेता लापता हो गए, जिनका कोई सुराग नहीं मिला है। अब यूट्यूब चैनल्स पर राष्ट्रवादी सिंधियों की रिहाई की माँग और गुमशुदा लोगों की जानकारी साझा की जा रही है। पाकिस्तान राज्य द्वारा अमानवीय यातना देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जनता इसके खिलाफ हथियार उठाने को तैयार दिख रही है। अन्य प्रांतों के मुकाबले सिंध अपेक्षाकृत शांतिप्रिय प्रांत रहा है और वहाँ हिंसा की घटनाएँ सीमित रही हैं। लेकिन सरकार और पुलिस की हिंसा के कारण प्रदर्शन और भी उग्र होते जा रहे हैं। सरकार की नीतियाँ अब उल्टा असर डाल रही हैं और उग्र आंदोलन की ज़मीन तैयार कर रही है। भारत द्वारा पश्चिमी सिंधु नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने से पाकिस्तान में जल-संतुलन और अधिक बिगड़ सकता है और पंजाबी-सिंधी संघर्ष और कटु हो सकता है। पाकिस्तान के किसी भी प्रांत में अब पंजाबी वर्चस्व को सहन करने की सहनशीलता नहीं बची है और अलग-अलग हिस्से इस दमनकारी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अतुर दिख रहे हैं।

यू ट्यूबर ज्योति पाक जासूस निकली

हिसार, 17 मई। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। हिसार पुलिस ने शनिवार को ज्योति को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, 15 मई को

- हरियाणा पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है।

उपाधीक्षक जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने ज्योति को उसके घर से गिरफ्तार किया। खुफिया ब्यूरो की टीम ज्योति से पूछताछ कर रही है। हिसार पुलिस के मुताबिक, ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी। वह सांशल मीडिया के माध्यम से भारत की गोपनीय जानकारी भेज रही थी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने पेपर लीक केस में जमानत याचिकायें खारिज कीं

जयपुर, 17 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला पर्यवेक्षक भर्ती-2018 का पेपर लीक करने वाले तुलछाराम और नकल कर परीक्षा पास करने वाली मंजू भामू की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राजकीय सेवा के लिए अभ्यर्थी दिन रात मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं। पेपर लीक से उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। वहीं, इन दिनों नकल के मामले काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में आरोपियों को

- आरोपी तुलछाराम पर, महिला पर्यवेक्षक भर्ती-2018 का पेपर लीक करने का और मंजू भामू पर नकल करके परीक्षा पास करने का आरोप है।

जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। मंजू भामू की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया कि उससे किसी तरह की बरामदगी नहीं हुई है। वहीं, उसे गिरफ्तारी का आधार तक नहीं बताया गया। वह गत 19 फरवरी से जेल में बंद है, जिससे चलते उसकी तीन साल की बच्ची की परवरिश प्रभावित हो रही है। इसलिए उसे जमानत दी जाए। तुलछाराम की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ 14 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन अधिकांश में वह दोषमुक्त हो चुका है और कई मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है। उसके खिलाफ जांच पूरी कर आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

न्यायाधीश बेला त्रिवेदी की सुप्रीम कोर्ट से विदाई कई वर्षों तक चर्चित रहेगी

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने परम्परागत विदाई समारोह व विदाई भोज का बहिष्कार किया

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 17 मई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने 16 मई 2025 को सेवा निवृत्त हो गईं, लेकिन बेहद अप्रत्याशित अंदाज में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से उन्हें कोई औपचारिक विदाई नहीं दी गई। यह लंबे समय से चली आ रही परंपरा का स्पष्ट उल्लंघन था, जो न्यायपालिका और वकीलों, विशेष रूप से दिल्ली के वरिष्ठ वकीलों, के बीच तनावपूर्ण संबंधों को उजागर करता है। हालांकि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उनके कई सहयोगियों ने न्यायमूर्ति त्रिवेदी के योगदान की प्रशंसा की, लेकिन

- एसोसिएशन की शिकायत ये थी कि न्यायाधीश बेला त्रिवेदी का रुख काफी कुछ सरकार में झुकाव रखता था तथा इस मुद्दे पर बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्यों-अधिकारियों के साथ उनके मतभेद न्यायालय में भी सार्वजनिक रूप से देखे गये थे।

- न्यायाधीश बेला त्रिवेदी, सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति व नियुक्ति पाने से पहले गुजरात हाई कोर्ट में जज थीं, उसी समय जब नरेन्द्र मोदी गुजरात के मु.मंत्री थे।

बार एसोसिएशन और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के एक वर्ग की ओर से टंडी प्रतिक्रिया ने उनके कार्यकाल के दौरान रहे विवादों को रेखांकित किया। कई अधिवक्ताओं ने, जिन्होंने मानवाधिकारों और जनहित से जुड़ी

अहम याचिकाएं जस्टिस त्रिवेदी की पीठ के समक्ष प्रस्तुत की थीं, उन्होंने न्याय दिए जाने को लेकर उनकी कार्यशैली पर गंभीर आपत्तियाँ जताईं।

एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा,

‘‘कोई भी न्यायाधीश, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता या सत्ता के प्रभाव में आता है, उसे न्यायपालिका के इतिहास में अच्छी यादों के साथ नहीं देखा जाएगा।’’ उनकी बात से सहमति जताते हुए एक और प्रख्यात वकील ने, न्यायमूर्ति त्रिवेदी को औपचारिक सम्मान न दिए जाने पर खेद प्रकट करते हुए कहा, ‘‘उनके ऊपर जो लोग सत्ता की सीढ़ियों पर बैठे हैं, वे भी न्यायिक मानकों के क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं।’’

गुजरात से ताल्लुक रखने वाली न्यायमूर्ति त्रिवेदी को मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी के निकट माना गया। उनके कार्यकाल के दौरान उनके कई फैसले विवादास्पद रहे और कई बार सुप्रीम कोर्ट (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वैटिकन सिटी जाएगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली, 17 मई। भारत सरकार का एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल वैटिकन सिटी में 18 मई को होने वाले पोप लियो चौदहवें के अधिष्ठान समारोह में भाग लेगा। इसमें राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश और नागालैंड

- राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और नागालैंड के डिप्टी सी.एम. यथुंगो पैटन का प्रतिनिधिमंडल पोप लियो चौदहवें के अधिष्ठापन समारोह में शामिल होगा।

के उपमुख्यमंत्री यथुंगो पैटन शामिल हैं। यहाँ जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस महत्वपूर्ण वैश्विक धार्मिक आयोजन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी अंतर-धार्मिक जुड़ाव, समुदायों के बीच परस्पर सम्मान को दर्शाती है।